DUSTRY AND DEPARMENT OF PUBLIC ENTERPRISES. (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Sick enterprises are generally suffering from fund crises. This sometimes may result in delayed payment of wages. Revival plans of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for the sick enterprises which are referable to the Board and revival plans for the other sick enterprises which have to be framed by the respective Managements and the administrative Ministries/Departments are expected to take care of this aspect also.

जर्मनी के साथ संयुक्त उद्यम

4733. श्री इश दत्त यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की सरकार में भारत में संयुक्त-उद्यम लगाने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (ग) 19 नवम्बर, 1991 को हुए औद्योगिक और आर्थिक सहयोग के लिए भारत-जर्मनी संयुक्त आयोग के 9वें सत्र के दौरान दोनों पक्षों ने संयुक्त उद्यमों के रूप में दोनों देशों के बीच व्यापार और उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामान्य हितों की बात कही थी ।

वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत और जर्मनी के उद्यमों के बीच स्वीकृत विदेशी निवेशी सहित विदेशी सहयोग प्रस्ताओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

अवधि	1990	1991	1992 (जुलाई तक)
(1) स्वीकृत कुल विदेशी सहयोगों की संख्या	134	157	125
(2) विदेशी पूंजी निवेश सहित विदेशी सहयोग के अनुमोदनों की संख्या	40	35	46
(3) स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश की कुल राशि (रु० लाखों में)	1951.22	4180.37	6147.43

उद्योगों की स्थापना किए जाने के कारण विस्थापित हुए परिवारों का पुनर्वास

4734. श्री राजूभाई ए. परमार :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों की स्थापना करते समय विस्थापित हुए परिवारों को पुनर्वास और रोजगार प्रदान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी इकाइयों/उद्योगों ने इन नियमों का पालन नहीं किया है और उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान पुनर्वास तथा रोजगार की व्यवस्था न

किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो ऐसी इकाइयों/उद्योगों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (ग) उद्योग लगाने के लिए भूमि के अधिग्रहण और जिन जिन लोगों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के कारण बेदखल कर दिया जाता है, उनके पुनर्वास तथा उनके रोजगार आदि की व्यवस्था करने का मूल उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है । भारत सरकार कोई आंकडे नहीं रखती ।

Sick Public Sector Enterprises

4735. DR. BAPU KALDATE:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some more public sector units have been added to the sick public sector undertakings list during 1990-91;

(b) if so, what are the details thereof stating the total number of sick units as on date; and

(c) the estimated number of workers affected with the adding up of the new sick units in the list of already identified public sector sick units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) As per the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA) the sick industrial units are referable to the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for formulation of revival/ rehabilitation plans. For the non-industrial sick units, the respective Managements and the administrative Ministries/Departments are required to formulate similar revival schemes. Details of these enterprises are given below:—

		1989-90	1990-91
1.	(a) Sick Public Enterprises referable to BIER under provision of SICA	50	54
	(b) Sick Public enterprises not referable to BIFR . . .	8	13
2.	Total number of sick Units	58	67
3.	Estimated number of workers involved (Reguiar employees) . .	4·08 (No. in lakhs)	3·97

कार का निर्माण करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी को पेशकश

4736. श्री शांति त्यागी :
श्री विनोद शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सस्ती तथा छोटी डीजल कार निर्माण करने के लिए एक फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी को पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित कार की कीमत मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति की पहुंच के भीतर होगी ।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।